



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 378 ]  
No. 378]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 1983/अश्विन 4, 1905  
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 1983/ASVINA 4, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास प्रायोग

अधिसूचना

नई दिल्ली 26 सितम्बर, 1983

सां०दा०नि० 746(अ).—औद्योगिक उपक्रमों का रजि-  
स्ट्रारण और अनुज्ञापन नियम 1952 का और सशोधन  
कार्य के लिए कुछ नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे  
कन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधि-  
नियम 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त  
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त धारा  
30 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों  
की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उसमें  
प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा यह सूचना  
दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र  
में प्रकाशन की तारीख से 60 दिन की अवधि की समाप्ति  
को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट  
तारीख से पहले उक्त प्रारूप की वास्तविकता व्यक्ति में प्राप्त  
होगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगा।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक उपक्रमों का  
रजिस्ट्रारण और अनुज्ञापन (सशोधन) नियम, 1983 है।

2 औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रारण और अनुज्ञापन  
नियम, 1952 में,—(i) नियम 3 के उपनियम (2) के स्थान  
पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात् —

“(2) प्रत्येक आवेदन के साथ वेतन और लेखा  
अधिकारी, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास  
विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के पक्ष में,  
भारतीय स्टेट बैंक, निर्माण भवन, नई दिल्ली  
पर लिखा गया 1000 ₹० का क्रम मांग देय  
ड्राफ्ट होगा।”

(ii) नियम 7 के उपनियम (3) के स्थान पर, निम्न-लिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) प्रत्येक आवेदक के साथ वेतन और लेखा अधिकारी, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के पक्ष में, भारतीय स्टेट बैंक, निर्माण भवन, नई दिल्ली पर लिखा गया 1000 रु० का क्रॉस मांग ड्राफ्ट होगा।”

[सं० 9/1/82-एलपी]

एस० एल० कपूर, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26 September, 1983

G.S.R. 746(E).—The following draft of certain rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, which the Central Government propose to make in exercise of the powers conferred by Section 20 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section 30, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of 60 days from the date of publication of this notification in the official Gazette.

2. Any objection or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft before the date so specified, will be taken into consideration by the Central Government.

## Draft Rules

1. These rules may be called the Registration and Licensing of Industrial Undertakings (Amendment) Rules, 1983.

2. In the Registration and Licensing of Industrial Undertaking Rules, 1952,

(i) in rule 3, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(2) Each application shall be accompanied by a crossed demand draft for Rs. 1000/- drawn on the State Bank of India, Nirman Bhavan, New Delhi, in favour of the Pay and Accounts Officer, Ministry of Industry, (Department of Industrial Development) Government of India, New Delhi.”

(ii) In rule 7, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(3) Each application shall be accompanied by a crossed demand draft for Rs. 1000 drawn on the State Bank of India, Nirman Bhavan, New Delhi, in favour of Pay and Accounts Officer, Ministry of Industry (Department of Industrial Development), Government of India, New Delhi.”

[No. 9/1/82-LP]

S.L. KAPUR, Joint Secy.